7. Compilation of Index of Industrial Production

8. Estimation of Crop area and Production

9. Compilation of Wholesale Price Index numbers

10. Compilation of Consumer Price Index numbers

11. Collection and compilation of Health, Morbidity and Mortality and Family Welfare Statistics

12. Collection and compilation of Education and Literacy statistics

13. Collection and compilation of Labour and Employment statistics

14. Collection and compilation of Housing statistics

15. Birth and Death registration and Population

16. Compilation of Electricity production and distribution statistics

17. Compilation of Environment and Forest statistics

18. Participation in the surveys of National Sample Survey Organization

19. Compilation of Transport statistics

20. Collection and compilation of Statistics for local area planning.

SHORT NOTICE QUESTION

Supply of chemical fertilizer to Gujarat

10. SHRI PARSHOTTAM KHODABHAI RUPALA: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILISERS be pleased to state:

(a) the action taken by Government to provide adequate quantity and timely supply of various Chemical Fertilizers to Gujarat for ensuing Monsoon season as during last rainy season farmers of Gujarat had suffered acute shortage of Potash;

(b) whether Government has received any communication from the State in this regard, if so, the action taken thereon; and

(c) how much quantity of various Chemical Fertilizers has been allocated to Gujarat State for ensuing Monsoon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Department of Agriculture & Cooperation (DAC) has assessed the requirement of Urda, DAP, MOP and Complex fertilizers for Government of Gujarat during Kharif 2012 as given in Table below:

(Figure in 000'MTs)

Product	Urea	DAP	MOP	NPK
April	125.00	65.00	12.00	41.00
May	170.00	110.00	14.00	60.00
June	215.00	110.00	22.00	59.00
July	240.00	70.00	20.00	48.00
August	230.00	55.00	16.00	40.00
September	220.00	70.00	16.00	27.00
Total	1200.00	480.00	100.00	275.00

The supply position during Kharif 2012 (April, 2012) as follows:

(Figures in 000'MTs)

Product	Pre-positioning in February and March	Opening Stock as on 01.04.12	April' 12 Receipts	Total Receipts	Requirement April' 12	% of total receipt against Requirement
1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7 (5/6*100)
Urea	0.00	8.19	143.91	152.10	125.00	121.68
DAP	92.32	18.28	31.50	142.10	65.00	218.61
MOP	0.00	2.62	2.81	5.43	12.00	45.25
NPK	147.30	23.77	36.04	207.11	41.00	505.14

As can be seen from the above table the availability of Phosphatic fertilizers in Gujarat till April, 2012 is very comfortable and supply plan as drawn by the companies for Kharif 2012 (May, 2012) has been conveyed to the state government which is as given below:

(Figures in 000'MTs)

May 2012

Product	Requirement	Opening Stock	Supply Plan	Tentative availability at the end of the month
Urea	170.00	36.20	170.00	206.20
DAP	110.00	35.69	82.90	118.59
MOP	14.00	2.77	21.00	23.77
NPL	60.00	46.13	24.95	71.08

(c) Department of Fertilizers (DOF) would continue to draw the monthly supply plans as indicated by companies in consultation with the respective State Governments and would try to make ensure that the supplies of fertilizer match the requirement projected by Gujarat.

श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रूपाला: सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो जवाब दिया है, उससे पता चलता है कि अप्रैल और मई के शुरू में ओपनिंग स्टॉक निल जैसा है। सर, सदन में और स्टैंडिंग कमेटी में भी यह मसला सभी सांसदों ने दलगत नीति से ऊपर उठकर कई बार उठाया है कि किसानों को समय पर खाद मिलनी चाहिए। एक साल में जितनी खाद की जरूरत होती है, सरकार उस साल में उतनी ही खाद मुहैया करवा देती है। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसको देखने से पता चलता है कि अप्रैल के शुरूआत में और मई के शुरूआत में स्टॉक निल है और अब मई का महीना खत्म होने जा रहा है तथा जून का महीना शुरू होने वाला है। इस समय किसान को अपनी फसल की तैयारी करनी है। इसके चलते केन्द्र की ओर से जरूरत के हिसाब से यूरिया क्यों नहीं पहुंचाया गया तथा यूरिया पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी?

श्री श्रीकांत जेना: सर, माननीय सदस्य ने गुजरात में अप्रैल के महीने में, यूरिया की availability के बारे में पूछा है, तो उनको बताना चाहूंगा कि ओपनिंग स्टॉक है। आप देखेंगे कि अप्रैल में यूरिया की जो रिक्वायरमेंट थी, उसी हिसाब से यूरिया है। नॉर्मली किसान को यूरिया की रिक्वायरमेंट जून के बाद होती है और अप्रैल में उसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। गुजरात के लिए 2011-12 में जो रिक्वायरमेंट थी, उसके हिसाब से यूरिया की कोई शॉर्टेज नहीं थी और इस साल भी यूरिया की कोई शॉर्टेज नहीं है।

श्री परुषोत्तम खोडाभाई रूपाला : सर, सवाल यह नहीं कि शॉर्टेज नहीं थी। मैं मानता हूं कि आप पूरे साल के हिसाब से इसकी पूर्ति कर देते हैं। यदि आप प्रश्न के उत्तर में देखेंगे तो यूरिया की उपलब्धि 152 मी.टन है और जरूरत 125 मी.टन है। आप यह भी कह

[श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रूपाला]

सकते थे कि जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा उनके पास है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका सही कारण क्या है? पिछले साल में जो यूरिया नहीं मिला, तो पड़ोसी राज्यों में जो अनयूटिलाइज्ड यूरिया था, उसको वहां की सरकार ने मंगवा कर स्टॉक में रखा है। आपके द्वारा जो यूरिया पहुंचाया गया था, वह 121 मी.टन है। इसमें यह होता है कि आप मंजूर कर देते हैं, बाद में वह मूवमेंट में जाता है और वह मूवमेंट समय से नहीं होती है। अन्य राज्यों के क्षेत्रों में जहां पर रेलवे का रैक नहीं होता है, वहां उसको वाया रोड पहुंचाया जाता है। उसको वाया रोड पहुंचाने में दिक्कत होती है। आपका वह आकलन सही है कि अभी इनको जरूरत नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन): आप क्वेश्चन पूछिए।

श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रूपाला: अभी से यदि स्टेट लेवल का स्टॉक नहीं होता है, ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन): आप प्रश्न पूछिए।

श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रूपाला: सर, स्टेट लेवल पर स्टॉक नहीं होता है, तो वह गांव में किसानों तक नहीं पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि आपने मंजूर कर दिया तो खेत में पहुंच जाएगा। पहले आप मंजूर करेंगे, बाद में उसका मूवमेंट होगा, फिर वह स्टेट में जाएगा और स्टेट से गांव तक पहुंचने में बहुत वक्त लगता है। जिस महीने उसकी जरूरत है, इससे आगे ...**(व्यवधान)**... होना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Please put the question.

श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रूपाला: इसके लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री श्रीकांत जेना: सर, जिस राज्य में स्टेट एजेंसीज़ advance pre-positioning के लिए पहले से ही खाद लेकर रखती है, वहां टाइमली सप्लाई के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे पंजाब में पंजाब फेडरेशन पहले से ही ले लेती है और Pre-positioning अपने पास गोदाम में रखती है। ट्रांजिट में शायद कहीं डिले हो सकता है। किसान को परेशानी न आए, इसलिए गुजरात में गवर्नमेंट की जो फेडरेशन है, अगर एक महीने का pre-positining करना चाहती है और कहती है कि यूरिया दे दे। तो हमको उसको देने में कोई कठिनाई नहीं है।

हमको उसको देने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन भारत सरकार के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका में इसको टाइमली पहुंचाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि रैक मूवमेंट में कहीं पर डिले हो सकता है, जैसा कि आपने बताया भी है। अगर गुजरात गवर्नमेंट इस काम के लिए, प्रिपोजिशनिंग के लिए अपने फेडरेशन को एक्टिवेट करे तो हमें फर्टिलाइजर पहुंचाने में कोई आपत्ति नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश गुजराल: उपसभाध्यक्ष जी, पंजाब में किसानों को बहुत परेशानी है ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवाल: उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न जानना चाहता हूं, वैसे समय-समय पर आपके बयान भी आते हैं कि यूरिया और डीएपी पर किसानों की सब्सिडी और कम की जाएगी, क्या आप यह बताएंगे कि पिछले दो वर्षों में, यूरिया और डीएपी पर किसान की कितनी सब्सिडी कम की गई, आज आप किसान को प्रति बोरी कितनी सब्सिडी दे रहे हैं और क्या आप उस सब्सिडी को भी वापस करेंगे? इसी विषय का एक दूसरा प्रश्न है कि आप 80 परसेंट खाद इम्पोर्ट करते हैं, हिन्दुस्तान में, यूरिया खाद के आपके कम से कम से 9 कारखाने हैं, जो बंद हैं, क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि उन 9 बंद कारखानों के सम्बन्ध में आपके विभाग की क्या नीति है? मंत्री जी, इसमें गोरखपुर भी सम्मिलित है।

श्री श्रीकांत जेना: सर, मुझे मालूम है। जहां तक सब्सिडी का सवाल है, सब्सिडी कम नहीं की गई है। यह न तो यूरिया पर कम की गई है और न ही PNK फर्टिलाइजर पर कम की गई है।

श्री नरेश अग्रवाल: कम नहीं की गई तो फिर खाद के दाम कैसे बढ़ गए? ...**(व्यवधान)**...

श्री श्रीकांत जेना: ये दाम इसलिए बढ़ गए ...**(व्यवधान)**... मैं आपको बता रहा हूं कि जो PNK फर्टिलाजर है, हम उसका इम्पोर्ट करते हैं। हमें, देश में 90 परसेंट PNK फर्टिलाइजर को इम्पोर्ट करना पड़ता है। जब इंटरनेशनल मार्किट में प्राइस बढ़ता है, तब हम सब्सिडी तो देते हैं, लेकिन सब्सिडी की जो फ्री मार्किट कर दी गई है, जैसे एमआरपी फ्री कर दिया गया है, DAP कॉम्पलेक्स फर्टिलाइजर और एम.ओ.पी. का भी यही है, तो इससे, नेचुरली मार्किट-ड्रिवन प्राइस हो गया है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी कम नहीं हो रही है। यूरिया में एम.आर.पी. है, यूरिया का प्राइस नहीं बढ़ाया गया है, यूरिया प्राइस constant है, लेकिन DAP और MOP का प्राइस इसलिए बढ़ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस बढ़ता रहता है। यदि 350 डॉलर का मार्किट प्राइस 600 डॉलर हो जाएगा, तो इतनी सब्सिडी देने से भी कुछ नहीं होगा। 2011-12 में सब्सिडी 90 हजार करोड़ तक गई है। सब्सिडी कभी कम नहीं हुई है, लेकिन उसके साथ-साथ ये परिस्थितियां हो रही हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवाल: आप कितने रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं?

श्री श्रीकांत जेना: मैं आपको इसकी डिटेल दे दूंगा, लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दो राज्य सरकारें हैं, एक गुजरात सरकार है और दूसरी उत्तर प्रदेश सरकार है, जहां पर अब वैट का टैक्स लगा दिया गया है। सारे देश में वही प्राइस है, लेकिन गुजरात और उत्तर प्रदेश में यह स्थिति बन गई है, इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो नई सरकार आई है, उसने जो 5 परसेंट वैट टैक्स लगाया है, उसको किसान के लिए विदड्रा कर ले, गुजरात गवर्नमेंट भी इस वैट को विदड्रा कर ले ताकि किसान को फायदा हो। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवाल: यह वैट पिछली सरकार ने लगाया था या इस सरकार ने लगाया है? ...**(व्यवधान)**...

श्री श्रीकांत जेना: यह पिछली सरकार ने लगाया है। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): No; please. ...*(Interruptions)*... Shri Rama Chandra Khuntia. ...*(Interruptions)*...

प्रो. अलका क्षत्रिय: वहां गुजरात में क्या कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रूपाला: केंद्र सरकार को ...**(व्यवधान)**... स्टेट्स में जो compensation देना था ...**(व्यवधान)**... आप उसमें गुजरात के साथ भेदभाव कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**... आप वह गुजरात को नहीं दे रहे हैं ...**(व्यवधान)**... अन्य राज्यों को दे रहे हैं ...**(व्यवधान)**... आप उनको रुपया देते हैं ...**(व्यवधान)**... उनको नहीं देते हैं ...**(व्यवधान)**... गुजरात की सरकार की वजह से हो रहा है ...**(व्यवधान)**... भाव डबल हो गया है ...**(व्यवधान)**... ये गुजरात की सरकार की वजह से हो रहा है ...**(व्यवधान)**... उनको भाव नहीं मिल रहा है ...**(व्यवधान)**...

प्रो. अलका क्षत्रिय: आप क्यों कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन): अलका जी, आप बैठिए ...**(व्यवधान)**... रूपाला जी, आप भी बैठिए ...**(व्यवधान)**... आप दोनों बैठिए ...**(व्यवधान)**... Let him answer. ...*(Interruptions)*...

श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रूपाला: गुजरात की सरकार को जो पैसा देना है, वह क्यों नहीं देते हैं ...**(व्यवधान)**...

प्रो. अलका क्षत्रिय: उपसभाध्यक्ष जी ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन): अलका जी, बैठिए, ...**(व्यवधान)**... रूपाल जी, बैठिए ...**(व्यवधान)**... No; please. ...*(Interruptions)*... It is your question. ...*(Interruptions)*...

श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रूपाला: रेट के हिसाब से जो रुपया है, ...**(व्यवधान)**... उसको क्यों नहीं देते हैं ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन): अलका जी, आप बैठिए ...**(व्यवधान)**... रूपाला जी, बैठिए ...**(व्यवधान)**... आपका ही क्वेश्चन है ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... रूपाला जी, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रूपाला: भारत सरकार को देना है ...**(व्यवधान)**... समय पर खाद नहीं पहुंचती है ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन): आप नाराज मत होइए, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रूपाला: और आप गुजरात सरकार को ब्लेम करते हैं? ...**(व्यवधान)**... पंजाब में खाद नहीं मिल रही है, ...**(व्यवधान)**... उत्तर प्रदेश में खाद नहीं मिल रही है ...**(व्यवधान)**... और पूरे देश में खाद नहीं मिल रही है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन): रूपाला जी, बैठिए। ...**(व्यवधान)**... खूंटिया जी, आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**... रूपाला जी, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... यह अच्छी बात नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रूपाला: इसका क्या करेंगे? ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन): रूपाला जी, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रूपाला: सरकार तो खेती करती है ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन): रूपाला जी, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... Please take your seats. ...*(Interruptions)*... Mr. Rupala, please take your seat ...*(Interruptions)*... Alkaji, please sit down. अलका जी, बैठिए। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़ बैठिए। Mr. Rupala, please take your seat. ...*(Interruptions)*... Mr. Rupala, please take your seat. I will have to adjourn the House. ...*(Interruptions)*... रूपाला जी, यह आप ही का क्वेश्चन है, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... It is your question. Do you not want to have it? ...*(Interruptions)*... Please sit down. It is your question and you don't want to hear it. ...*(Interruptions)*... Please don't do this, Mr. Rupala. ...*(Interruptions)*... No, no; please ...*(Interruptions)*... Order in the House, please. Now, Mr. Khuntia, put your question. ...*(Interruptions)*... Allow your own question. रूपाला जी, यह आप ही का क्वेश्चन है। खूंटिया जी, आप बोलिए।

श्री नरेश अग्रवाल: सर, इस पर आधे घंटे की चर्चा करा लीजिए, हम नोटिस दे देते हैं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन): ठीक, है, आप नोटिस दे दीजिए।

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA: Sir, the hon. Minister has said that the subsidy that is being given amounts to more than Rs.90,000 crores, but I wish to draw his attention to the fact that the benefit of this subsidy is not reaching the farmers. I would like to specifically know from the hon. Minister whether the Government would start a new system of providing this subsidy directly to farmers. I would like to particularly know how much demand for fertilizers was made by the Odisha Government this year. I would also like to know whether it is a fact, as frequent reports appearing in newspapers allege, that the Central Government was not fulfilling the demand for fertilizers made by Odisha. What is the stand of the Central Government there? I would also like to know whether Government have taken a decision to reopen the fertilizer plant at Talcher, which had been closed.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I would like to take half-a-minute here. This is a very serious issue. I think, the hon. Minister, and all of us, need to realize that we must not make it a political issue of one State or one Government. The farmers are suffering. I think, the same gravity needs to be maintained in the Minister's reply as well.

SHRI SRIKANT JENA: Sir, I fully share the hon. Member's view, and we are very serious about this issue. The Government, which is giving subsidies ranging from Rs. 90,000 crores to one lakh crore rupees to farmers in India, is really very sincere. It is not as if we are not serious. We get more serious when the

[SHRI SRIKANT JENA]

international prices of the DAP and PNK fertilizers go up, and naturally, we request the State Governments to take away the burden of subsidies a little from the Central Government. And even they have the same plan. They should see to it that there should not be any black marketing, and there should not be any diversion of fertilizers or urea to the industries. According to information, two lakh two million tonnes of Urea go to the industries, and the State Governments are keeping quiet on that aspect. We have been writing letters after letters to them, and no action is being taken at their end. Therefore ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश अग्रवाल: सर, मंत्री जी सीधे-सीधे राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। माननीय मंत्री जी हर चीज के लिए ...**(व्यवधान)**... ये अपनी जिम्मेदारी ...**(व्यवधान)**... ये तो सीधे-सीधे अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I think, the hon. Minister has ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Let him finish. ...*(Interruptions)*... Let him finish. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश अग्रवाल: किसान को उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है और यूरिया का दाम बढ़ रहा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय मंत्री जी, आप पूरे हिन्दुस्तान के मंत्री हैं, किसी पार्टी के मंत्री नहीं हैं।

श्री नरेश अग्रवाल: आप इस तरीके से दाम बढ़ा कर ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन): अग्रवाल जी ...**(व्यवधान)**... अग्रवाल जी, पहले मंत्री जी को बात खत्म करने दो ...**(व्यवधान)**... Let him finish. ...*(Interruptions)*... अग्रवाल जी, आपका क्वेश्चन हो गया है ...**(व्यवधान)**... Let him complete the reply. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश अग्रवाल: आपके इस जवाब से हम और हमारा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(At this stage, some hon. Members left the Chamber)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): You give reply to Mr. Khuntia's question. ...*(Interruptions)*...

SHRI SRIKANT JENA: Sir, there are three very serious issues raised by Shri Rama Chandra Khuntia. One is, whether the Government is contemplating to give subsidy to the farmers directly. This was announced by the Finance Minister in his Budget Speech that our intention is to give the subsidy to the farmers directly. There is a Committee under the Chairmanship of Mr. Nandan Nilekani, and they

have already worked out a scheme of things. Now, we have decided that from June onwards, up to the retail level, the subsidy will be checked. Once the retailer gets the fertilizer, then the subsidy will be released. The next point is, from retailer to the farmer; to identify as to who are the real farmers is a difficult proposition. So, up to the retail level, we are now going to roll out it by the end of June. Already, a model has been worked out. The pilot programme is on. We are hopeful that it can be replicated throughout the country after June. Regarding the Talcher Unit, along with other sick units which have been closed down, the Government has already taken a decision to again revive those units. In the national interest, the Cabinet has already directed the Department of Fertilizer to work out which are the units which can be taken up through public sector route, and also through PPP route. It has been decided to take up three units through public sector route. Talchar is one of them. We are on the right track and I am sure that it will be materialized soon. So far as the fertilizer to Odisha is concerned, there is no shortage of fertilizer to Odisha, and whatever they have asked for, that has been supplied to.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Shri Upendra Kushwaha, not asking. Okay.

श्री भारतसिंह प्रभातसिंह परमार: उपसभाध्यक्ष जी, गुजरात में कृषि का ग्रोथ रेट 11% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। केवल वैट के कारण भाव डबल नहीं हुए, डीएपी में हम रॉ-मैटीरियल इम्पोर्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से भी भाव डबल हो गए हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह भाव बढ़ते जा रहे हैं, क्या उसी तरह आप सब्सिडी भी बढ़ाएंगे? यदि नहीं, तो क्या आप फर्टिलाइज़र के आल्टरनेटिव, ऑर्गेनिक कृषि में आगे बढ़ेंगे?

श्री श्रीकांत जेना: डीएपी का जो रॉ-मैटीरियल है, वह Rock Phosphate है, यह आप सभी को मालूम है। Rock Phosphate कुछ क्वांटिटी में हमारे देश में राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिलता है, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। उसको एनरिच करके हम कुछ यूनिट single super phosphate के लगाते हैं, लेकिन मोस्टली हमें Rock Phosphate बाहर से लाना पड़ता है। इसके चलते अगर Rock Phosphate का प्राइस बढ़ गया, तो यहां डीएपी और एनपीके फर्टिलाइज़र का प्राइस भी बढ़ जाता है।

जहां तक एमओपी का सवाल है, एमओपी एक international cartel है और उस cartel को तोड़ना बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं, लास्ट ईयर हमने कोशिश की कि हम कम से कम इतना जरूर करेंगे कि एमओपी इतने ज्यादा प्राइस पर नहीं खरीदेंगे। एक तरफ डोमेस्टिक डिमांड है कि एमओपी लाइए, लेकिन दूसरी तरफ जो international cartel है, वह प्राइस बढ़ाता रहता है, इसलिए हमने इसके बीच के रास्ते को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिससे प्राइस थोड़ा गिरा।

जहां तक फर्टिलाइजर के ऑल्टरनेटिव का सवाल है, इसके बारे में कृषि मंत्री जी ने खुद ही बताया है कि हमारी जमीन को जितना नुकसान केमिकल फर्टिलाइज़र से हो रहा

[श्री श्रीकांत जेना]

है, उसके लिए ज्यादा सब्सिडी बायो-फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को दी जाएगी। उनका यह आश्वासन मैं कल-परसों ही लोक सभा में सुन रहा था, कृषि मंत्री जी खुद ही चिन्तित हैं कि इसको कैसे बढ़ाया जाए, ताकि कैमिकल फर्टिलाइज़र से हमारा ध्यान बायो फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर जाए।

PAPERS LAID ON THE TABLE

I. Report and Accounts of the HAL, Pune and related papers.

II. MoU between Government of India and various Insecticides Drugs and Pharmaceuticals companies.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): Sir, I lay on the Table:—

I. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of Section 619 A of the Companies Act, 1956:—

(a) Fifty-seventh Annual Report and Accounts of the Hindustan Antibiotics Limited (HAL), Pune, for the year 2010-11, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above. [Placed in Library. *See* No. L.T. 6901/15/12]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals) and the Hindustan Insecticides Limited (HIL), for the year 2012-13. [Placed in Library. *See* No. L.T. 6897/15/12]

(ii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Pharmaceuticals) and the Rajasthan Drugs and Pharmaceuticals Limited (RDPL), for the year 2012-13. [Placed in Library. *See* No. L.T. 6900/15/12]

(iii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Pharmaceuticals) and the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited (IDPL), for the year 2012-13. [Placed in Library. *See* No. L.T. 6899/15/12]